योजना लागू की गई है, लेकिन केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई इन्वाइटी नहीं गया है। यह चीज, जैसे और ढीले-ढाले काम प्रदेश सरकारों के चलते हैं, उसी स्तर पर चलती है। इसको विशेष महत्व देना चाहिये और हर महीने इस की मीटिंग होनी चाहिये। जिले में या प्रदेश में जो सब से बहतरीन कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामसेवक हो, पंचायत मंत्री हो, या ब्लाक अधिकारी हों, जो सब से अच्छे हों, उन को इस काम में लगाना चाहिये और प्राथमिकता के आधार पर, सामरिक-स्तर पर इस स्कीम को लाग करना चाहिये।

एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वैसे बतलाया गया है कि देश में अन्न की कोई कमी नहीं है, अन्य के भण्डार बहुत हो गये है, लेकिन अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमरीका से एक समझौता हुआ है, उस के दूसरे डिप्लोमेटिक कारण हो सकते है, लेकिन आकड़े जो दिये गये है कि हमारे यहां देश में अन्न की प्रचुरता है, आधिक्य है, अन्न के दाम सस्ते हो गये हैं, इन सब बातो के होते हुए भी अभी अमरीका से समझौता किया गया है, जिस के अन्तर्गत चार लाख टन गेहूं जिस का मूल्य 8300 सिलियन डालर है, उस का आयात किया जायगा। 1975 में भी अमरीका से 46.31 लाख टन गेहूं मंगाया गया।

दूसरी चीज यह है कि जो दाम गिर गये हैं उन को बढ़ाने के लिये, काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिये, जो सिंगल स्टेट जोन्स बना दिये गये हैं, यानी गेहूं एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं भेजा जा सकता है, यह प्रतिबन्ध अगर हटा दिया जाय तो न केवल काश्तकारों को ज्यादा दाम मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं, उन को भी राहत मिलेगी। यदि देश भर का एक बाजार बना दिया जाय, तो यह दिक्कत नहीं होगी।

जहां तक खाद का सवाल है—सभी ने कहा है कि खाद बहुत महंगी है। हमारे मंत्री जी ने इस विषय में बहुत कुछ काम किया है। मैं भी अन्य साथियों के साथ उन की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहता हूं कि खाद के दाम घटे हैं जिससे काश्तकारों को फायदा हो।

फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के जो कर्मचारी हैं, वे बिलकुल नवाब है। जिन को स्वेत हाथी कहा जाता है, वे बिलकुल वैसे ही हैं। न तो वे समय पर खरीदना शुरू करते हैं और न समय पर दाम देते है, इन की साठ गाठ और साजिश स्थानीय बनियो के साथ होती हैं। इस लिये आप इन के ऊपर कड़ी निगरानी रखने का प्रयास करें। वरना आप की यह स्कीम, जिस तरह से आप इस को कारगर बनाना चाहते हैं, कारगर नहीं हो पायगी।

18.04 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
(SIXTY-FIRST REPORT)

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Sir, I beg to present the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee.